shortage of staff in IRCTC, IRCTC can easily ask the Railways for providing more staff on deputation. But the IRCTC management has bent upon to privatise the concern. While lodging protest against the outsourcing in IRCTC beyond the knowledge of Parliament, I demand immediate stoppage of all attempts of outsourcing in Indian Railways and IRCTC. Thank you.

Pathetic Condition of National Highways in Bihar

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): महोदय, बिहार में सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है। सड़क और गड्ढे में अंतर करना अत्यंत कठिन है। यदि कोई नया वाहन खरीदता है तो वह वाहन बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है और उस की हालत जर्जर हो जाती है। आए दिन गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने और उन दुर्घटनाओं में लोगों के मरने की घटनाएं घटती रहती हैं। चाहे राज्य राजमार्ग हों या राष्ट्रीय राजमार्ग, दोनों की दशा एक जैसी है। अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ से सड़कों की मरम्मत की जाती है और दूसरी ओर से मरम्मत की गई सड़कें टूटने लगती हैं। इस का कारण है मरम्मत और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव। साथ ही, इन की निगरानी का कोई ठोस इंतजाम भी नहीं है। जो ठेकेदार इस काम को करते हैं तथा जो अधिकारी इस पर निगरानी रखते हैं, उन दोनों में सांठ-गांठ है और इसी वजह से इन सड़कों की यह स्थिति है।

जहां देश में कुछ राज्यों में सरकार द्वारा 6 लेन अथवा 8 लेन की सड़कें बनायी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति ठीक नहीं है। इन की मरम्मत का काम समय पर नहीं कराया जा रहा है जिस की वजह से बिहार में सड़क परिवहन बहुत ही दयनीय स्थिति में है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की तुरन्त मरम्मत कराने के लिए आवश्यक धन मुहैया कराए तथा इस धन के व्यय पर निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था करें।

Request to NEC to accept more Projects forwarded by North-eastern States

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): This is a fact that as many as 582 projects have been forwarded by the North-eastern States to the NEC during 2005-06 and 2006-07. Out of these projects, only 195 proejcts have been accepted by the NEC. A large number of proejcts, to the tune of 387, has not been accepted. It is seen that the unaccepted projects focus on developing the States in agriculture, forestry, tea-plantation, food-processing, pisciculture, education, sports, power sector, irrigation, health care, industries, infrastructure and in many such other aspects that will enable the States in enriching economy and affording employment opportunities for the youth in the respective States. By sending the proposals, the States have tried to accommodate their right concerns.